

संपादकीय विपक्ष की गारंटियों के बावजूद एनडीए को बहुमत

मौद्रिक नीति यथावत

A portrait of Prime Minister Narendra Modi, wearing glasses and a colorful patterned shirt, pointing his right index finger upwards. The Indian flag is visible in the background.

ડા. આંશુની મહાજન

आत्मानं भर भारत नात के तहत देश में विनामाण उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी फलीभूत हो रहे हैं, लेकिन इस दिशा में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी, ताकि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। देश में बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करने होंगे। यह सही है, पारंपरिक रोजगार प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन तकनीक के साथ तालमेल बने 2024 का आम चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं की अपेक्षा से कम सीटें पाने में सफल रही, लेकिन एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश जरूर मिला है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की अगुआई वाला एनडीए पिछले दस सालों के अपने काम और प्रदर्शन पर बोट मांग रहा था, वहाँ दूसरी तरफ विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन मोदी सरकार के दौरान महांगई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहा था। एक तरफ नरेंद्र मोदी 'जीवन को आसान बनाने' की गारंटी और अपनी नीतियों के साथ लोगों तक पहुंच रहे थे, जिसमें गरीबों के लिए आवास, अगले 5 सालों तक गरीबों को मुफ्त राशन, गरीबों के साथ-साथ 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत मुफ्त इलाज, किसान सम्पादन निधि और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना शामिल था। लेकिन कांग्रेस जो कि इंडी गठबंधन की मुख्य पार्टी थी, वह पिछले चुनावों की तरह ही, हर गरीब परिवार को एक लाख रुपए की राशि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, जाति आधारित सर्वेक्षण करके धन का पुनर्वितरण (जनसंख्या के अनुसार) आदि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में थी। इंडी गठबंधन में शामिल अन्य क्षेत्रीय दल भी मुफ्त योजनाओं का लालच देकर जनता को लुभा रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने मुफ्त योजनाओं के लिए बोट नहीं दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को जीत दिलाई। यह साबित करता है कि भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी के दस साल के कार्यकाल के दौरान अपनाई गई नीतियों का समर्थन करके एनडीए को विजयी



बनाया है, हालांकि उस भारी बहुमत के साथ नहीं, जिसका दावा सत्तारूढ़ गठबंधन कर रहा था, खासकर तीन बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में। हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गरीबों के लिए बड़ी संख्या में कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं, जिनके लाभार्थियों ने स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। लाभार्थियों की बात करें तो 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए पक्के मकानों का निर्माण नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। गौरतलब है कि जो गरीब परिवार पहले कच्चे या अर्ध-कच्चे मकानों में रहते थे, उनके लिए पिछले कुछ सालों में करीब 3 करोड़ ग्रामीण और एक करोड़ शहरी मकान बनाए गए। अगर पांच लोगों के परिवार को माना जाए तो करीब 20 करोड़ लोग इस योजना के लाभार्थी रहे हैं। समझा जा सकता है कि इस योजना ने उन गरीब परिवारों की कुशलता और जीवन स्तर में बड़ा बदलाव लाया है। स्वाभाविक रूप से एनडीए को इन लाभार्थियों का समर्थन मिला है। इसके साथ ही गरीबी के कारण एलपीजी कनेक्शन से वर्चित 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत न सिर्फ धुएं से मुक्ति मिली है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव आया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन

लाभार्थियों ने भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन किया है। वैसे तो महिला स्वाभिमान के प्रतीक शौचालयों के निर्माण को सामाजिक क्रांति माना जा सकता है, लेकिन इसमें कोई सदेह नहीं कि इस योजना के कारण खुले में शौच से मुक्त हुई महिलाओं का समर्थन भी मौजूदा सरकार चला रही पार्टियों को मिला होगा। लगभग पूरे देश को नल से जल और शत-प्रतिशत बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना किसी क्रांति से कम नहीं माना जा सकता। करीब 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन और किसानों को 6 हजार रुपए प्रति वर्ष की राशि जारी रखने की गारंटी भी एक लोकप्रिय कदम माना जा रहा है। समझना होगा कि किसान सम्मान निधि को छोड़कर, जिसका असर करीब 75000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सरकारी खर्च पर फैलता है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई भी अन्य योजना नकद वितरण वाली नहीं थी। इससे पहले भी कांग्रेस ने किसानों के 70000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए थे और 2024 में भी इसी तरह की घोषणा की गई थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद हर गरीब परिवार को सालाना 72000 रुपए देने का बादा किया था और तब भी कांग्रेस को लोकसभा में सिर्फ 52 सीटें ही मिलीं। यानी

तब भी लोगोंने को कांग्रेस की नकद वितरण योजना को नकार दिया था। इस बार कांग्रेस ने चुनाव के दौरान हर गरीब परिवार को सालाना एक लाख रुपए देने का वादा किया था और इसका खूब प्रचार भी किया था। हालांकि, कांग्रेस के इस वादे के क्रियान्वयन को लेकर लोगों में काफी संदेह था और कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर, सरकार में शामिल होने के लिए जातुर्दसंख्या से काफी कम 100 से कुछ कम ही रहीं। एक तरफ जनता द्वारा नकद वितरण योजना को नकारना और दूसरी तरफ मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं पर दिखाया जा रहा भरोसा, देश के मतदाताओं और लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है। यह सच है कि पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। और देश दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन यह भी सच है कि हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच असमानता अभी भी बनी हुई है। हालांकि, अत्यधिक गरीबी में काफी कमी आई है, लेकिन मोदी सरकार के पहले नौ वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के बावजूद बहुआयामी गरीबी से पीड़ित लोगों की संख्या वर्ष 2023 तक 12 करोड़ बनी हुई थी। यह सही है कि राजकोषीय सूझबूझ के कारण सरकार का पूँजी निवेश बढ़ रहा है, देश में बड़ी मात्रा में बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है, जिससे देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और आप लोगों के जीवन को आसान बनाने में सफलता मिल रही है। दूसरी ओर, तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन लेन-देन दुनिया में कहीं और की तुलना में भारत में कहीं अधिक हो रहा है, सरकार अधिक से अधिक पेटेंट देने में भी सफल रही है, और अंततः: वर्ष 2014 में केवल 4227 पेटेंट की तुलना में वर्ष 2024 में 1.03 लाख पेटेंट दिए गए, जो देश में नवाचार में विकास को दर्शाता है। हालांकि, उत्पादों के निर्माण में हमारी निर्भरता अभी भी विदेशों पर बनी हुई है। आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत देश में विनिर्माण उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी फैसीभूत हो रहे हैं।

विशेष लेख

वैचारिक मतभेदों को व्यक्त करने का घृणित तरीका....

प्रियंका सौरभ

ડા. જયંતીલાલ ભંડારી

वैचारिक मतभेदों को व्यक्त करने का घृणित तरीका, खासकर जब आप वर्दी पहने हों। 'शर्मिंदगी और हैरानी' इस बात की है कि ये काम सीआईएसएफ की सुरक्षाकर्मी ने किया है जो लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं। क्या ये कंगना के खिलाफ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर प्लांड अटैक है? सांसद पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुआ हमला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर एक सुरक्षाकर्मी द्वारा, जिन पर सुरक्षा का जिम्मा होता है। अपनी शिकायत को रखने का और भी सभ्य तरीका होता है।' भारतीय राजनीति और सामाजिक जीवन में हम अक्सर इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं। 'थप्पड़' कहने से हिंसा की गंभीरता कम होती है और हिंसा के शिकार की कमजोरी ज्यादा उजागर होती है। थप्पड़ से किसी की जान नहीं जाती, उसकी निष्क्रियता अधिक प्रकट होती है। उसमें किसी योजना की जगह एक प्रकार की स्वतन्त्रता का तत्व होता है। कहा जा सकता है कि थप्पड़ माने वाले की मंशा सिर्फ नाराजगी का इजहार होता है। राजनीति और सिस्टम (लोकतंत्र या तानाशाही) में विरोध जायज है और यही विरोध तरह तरह के स्वरूपों में हमारे सामने आता रहता है। थप्पड़ या स्याही हमला भारतीय राजनीति में कोई नया किस्सा नहीं है। पहले भी हमारे नेता इन हमलों का दंश झेलते रहे हैं। इतना ही नहीं कई नेताओं पर जूता उछले जाने की घटनाएं भी हुई हैं। लोकतंत्र लोगों को विरोध प्रदर्शन की आजादी देता है और लोग विरोध के नए-नए तरीके खोज लाते हैं। कभी विरोध में अंडे, टमाटर फेंके जाते हैं, तो कभी जूते-चप्पल 'कंगना ने किसान आंदोलन के खिलाफ में कृष्ण

गति से आगे बढ़ीं। उल्लेखनीय कि हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने वर्ष 2023-24 में देश की विकास दर 8.2 पीसदी रहने संबंधी रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक अर्थिक व वित्तीय बाजार मजबूत हो रहे हैं। भारत के वित्तीय और गैर वित्तीय क्षेत्रों के दमदार बढ़ी-खाते भारत की अर्थिक ताकत बढ़ा रहे हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा भारत सरकार को दिया गया रिकॉर्ड लाभांश, वैश्विक अर्थिक संगठनों के द्वारा भारत के विकास के नए-नए प्रभावी विश्लेषण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन सबके साथ-साथ नई सरकार से देश की अर्थव्यवस्था को नई शक्ति मिलने की संभावनाओं से देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ने के शुभ संकेत देते हुए दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि हाल ही में दुनिया की प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने भारत की मजबूत अर्थिक वृद्धि, तेज अर्थिक सुधार और बढ़ती राजकोषीय मजबूती के महेनजर भारत की रेटिंग को स्थिर यानी स्टेबल से बदलकर पॉजिटिव कर दिया है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि पिछले तीन साल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत वास्तविक वृद्धि दर 8.1 पीसदी सालाना रही है और अब यह विकास दर अगले तीन साल में लगातार 7 पीसदी के करीब होगी। दुनिया के प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट बैंकर गोल्डफैन सैक्स ने अपनी नई रिपोर्ट में कैलेंडर

वर्ष 2024 में भारत की विकास दर को बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में विकास दर बढ़ने संबंधी अन्य महत्वपूर्ण नई रिपोर्टों के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 6.8 प्रतिशत, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 7 प्रतिशत तथा विश्व बैंक ने 7.5 प्रतिशत विकास दर रहने के अनुमान व्यक्त किए हैं। देश और दुनिया के प्रमुख अर्थ विशेषज्ञों का मत है कि भारत की विकास दर आगामी दशक तक 6.5 से 7 प्रतिशत के स्तर पर दिखाई देगी। विभिन्न अर्थिक रिपोर्टों में इस बात को भी रेखांकित किया जा रहा है कि भारत में वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) संग्रह 17.7 पीसदी बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह से 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) उच्चतम स्तर पर रहा है। इसका आकार 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.7 पीसदी अधिक है। कर संग्रह के ये चमकीले आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज उछाल और व्यक्तियों तथा कारपोरेट सेक्टर की आमदनी में वृद्धि को दर्शाते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि जिस तरह से रिजर्व बैंक के ऑफ ईडिया (आरबीआई) के द्वारा हाल ही में भारत सरकार के लिए अब तक के सबसे अधिक लाभांश की राशि सुनिश्चित की गई है, वहीं दूसरी ओर देश के शेयर बाजार ने पिछले 10 वर्षों में जो ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, उससे दुनिया भर में भारत के नए तेज विकास की नई संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए लाभांश देने की मंजूरी दी है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सरकार ने रिजर्व बैंक और सरकारी बैंकों के लाभांश से 1.02 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया था। ऐसे में रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाने वाला लाभांश बजट अनुमान की तुलना में 107 पीसदी ज्यादा है। यह एक तरह से सरकार के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 1.09 लाख करोड़ रुपए के अप्रत्याशित लाभ जैसा है। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक ने पहली बार आकस्मिक जोखिम बफ (सीआरबी) बढ़ाकर 6.5 पीसदी कर दिया गया है, जो पहले 6 पीसदी था। रिजर्व बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, इसीलिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आकस्मिक जोखिम बफ बढ़ाकर 6.5 पीसदी करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार को रिकॉर्ड लाभांश के दिए जाने के निर्णय और वैश्विक अर्थिक संगठनों व वैश्विक क्रेडिट एजेंसियों के द्वारा वर्ष 2024-25 में भारत की ऊंची विकास दर के अनुमानों के बाद भारतीय शेयर बाजार को लाभ मिला। यह उल्लेखनीय है कि शेयर बाजार और निवेशकों को उमीद थी कि 4 जून के लोकसभा चुनाव परिणामों से भाजपा और एनडीए को भारी बढ़त मिलेगी।

नई सरकार से मजबूत होगी आर्थिकी...

चूंकि भारत लगातार चालू खाते के घाटे से जूँझ रहा है और भारत को विदेशी बचतों को हासिल करने की जरूरत है, इसलिए एफडीआई भारत में विदेशी बचतों के सबसे टिकाऊ स्रोत के रूप में लाभप्रद होगा। भारत की विकास दर के 8.2 प्रतिशत रहने से नई सरकार को व्यव प्रबंधन में मदद मिलेगी चार जून को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब बनने वाली एनडीए के तीसरे कार्यकाल की नई सरकार देश को अर्थिक विकास की डाग पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। निश्चित रूप से देश को एक बेहतर अर्थिक परिवेश के साथ बेहतर मानसून की सौगातें विरासत में मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। इस्थिति यह है कि देश की बेहतर अर्थिकी के परिप्रेक्ष्य में दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां यह कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि भारत में कोई भी सरकार बने, अब अर्थिकी तेज गति से मजबूत होगी। खास बात यह भी है कि 7 जून को एनडीए के संसदीय बोर्ड की बैठक में जिस तरह से गठबंधन के समर्थक नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सराहना दी गई और विकसित भारत के लिए हर तरह का योगदान देने का संकल्प दोहराया गया, उससे निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था और तेज प्रतिशत कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में विकास दर बढ़ने संबंधी अन्य महत्वपूर्ण नई रिपोर्टों के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 6.8 प्रतिशत, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 7 प्रतिशत तथा विश्व बैंक ने 7.5 प्रतिशत विकास दर रहने के अनुमान बताए हैं। देश और दुनिया के प्रमुख अर्थ विशेषज्ञों का मत है कि भारत की विकास दर आगामी दशक तक 6.5 से 7 प्रतिशत के स्तर पर दिखाई देगी। विभिन्न अर्थिक रिपोर्टों में इस बात को भी रेखांकित किया जा रहा है कि भारत में वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) संग्रह 17.7 फीसदी बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह से 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) उच्चतम स्तर पर रहा है। इसका आकार 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.7 फीसदी अधिक है। कर संग्रह के ये चमकीले आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज उछाल और व्यक्तियों तथा कॉर्पोरेट सेक्टर की आमदानी में वृद्धि को दर्शाते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के द्वारा हाल ही में भारत सरकार के लिए अब तक के सबसे अधिक लाभांश की राशि सुनिश्चित की गई है, वहाँ दूसरी ओर देश के शेयर बाजार ने पिछले 10 वर्षों में जो ऊंचाइयां प्राप्त की नई संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए लाभांश देने की मंजूरी दी है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सरकार ने रिजर्व बैंक और सरकारी बैंकों के लाभांश से 1.02 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया था। ऐसे में रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाने वाला लाभांश बजट अनुमान की तुलना में 107 फीसदी ज्यादा है। यह एक तरह से सरकार के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 1.09 लाख करोड़ रुपए के अप्रत्याशित लाभ जैसा है। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक ने पहली बार आक्रिमक जोखिम बफ (सीआरबी) बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया गया है, जो पहले 6 फीसदी था। रिजर्व बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, इसीलिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आक्रिमक जोखिम बफ बढ़ाकर 6.5 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार को रिकॉर्ड लाभांश के दिए जाने के निर्णय और वैश्विक अर्थिक संगठनों व वैश्विक क्रेडिट एजेंसियों के द्वारा वर्ष 2024-25 में भारत की ऊंची विकास दर के अनुमानों के बाद भारतीय शेयर बाजार को लाभ मिला। यह उल्लेखनीय है कि शेयर बाजार और निवेशकों को उम्मीद थी कि 4 जून के लोकसभा चुनाव परिणामों से भाजपा और एनडीए को भारी बढ़त मिलेगी।

-डॉ. सुनील जैन संचय

रात्रि भोजन त्याग, प्रतिदिन देवदर्शन और पानी छानकर पीना ये जैनी के चिह्न माने गए हैं। इस लेख में हम पानी छानकर पीने की अपनी आदर्श कुलाचार संसाधनों के बारे में बढ़ावा देंगे।

बुद्धेलखंड में बिलछानी भी कहते हैं। छने जल की मर्यादा एक मुहूर्त अर्थात् 48 मिनट भी गया है कि पानी पिओ छानकर, गुरु मानो जानकर। पीने छानकर पीने की आदर्श परंपरा आज हमारी आपन भा एस धामक आयोजन देख हाग जसम नगर में शोभायात्रा निकलने पर बोतल बंद पानी की खाली बोतलें शहर में इधर-उधर पड़ी आपकी शोभायात्रा,

की भावना है। जैन धर्म के अनुसार जल में त्रस जीव भी होते हैं। विज्ञान के अनुसार एक बूँद पानी में 36450 जीव होते हैं, त्रस जीवों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। हमें पानी तो पीना ही है, पानी के बिना रहना सम्भव नहीं है। तो एक व्यवस्था बताई गयी कि जीवदया का पालन करने की भावना से आप जल के स्रोत से जल को निकालो। उसे गढ़े छें से छानो और बड़े इत्मिनान के साथ आप पानी को जीवाणी करो यानि वो पानी के छें को छेने पानी से धोकर वापस जलाशय में ले जाओ और उसे डेल दो और इसके पीछे की जो भावना है वह है झुं जीव दया का अनुपालन! इस दृष्टि से सच्चे अर्थों में पानी छानने का लाभ उनको मिलता है जो जैन समाज से विलुप्त सी होती जा रही है, जलगालन विधि के बारे में तो आज की ज्यादातर आधुनिक पीढ़ी को पता ही नहीं है। अब तो नलों में लगी थेली को छेने पानी की मान्यता सी मिल गयी प्रतीत होती है और वह भी अनेक दिनों तक एक नल में लगी रहती है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि आज ज्यादातर हमारे धार्मिक आयोजनों में भी बिना छेने पानी का धड़क्के से उपयोग हो रहा है और यह सब उस आयोजन में सत्रिध्य प्रदान कर रहे संतों और विद्वानों को भी पता होता है। निश्चित रूप से यह बहुत ही चिंतनीय है।

आज धार्मिक आयोजनों में बोतल बंद पानी का प्रचलन खबर हो गया है यहां तक देखा गया है कि एक जूलूस की निशानी बता रहे होंगे। जैन समाज की विभिन्न धार्मिक बैठकों में भी अब बोतल बंद पानी/आरओ का पानी का प्रयोग फैशन सा बन गया प्रतीत होता है। धार्मिक आयोजन में जो भोजन होता है उसमें भी इसी पानी के प्रयोग का प्रचलन बढ़ रहा है। बड़े -बड़े धार्मिक महोत्सवों में तो अब यह बोतल बंद पानी सस्ते दामों में भी बांटकर पुण्यार्जन किया जाने लगा है। पानी छानकर पीने वे जलगालन विधि में आई इस विकृति पर हमें गंभीरता पूर्वक चिंतन करना होगा। कम से कम धार्मिक आयोजनों में तो अनछेजे जल का प्रयोग बंद होना चाहिए। इसके लिए हमारे आराध्य सभी पञ्च मनिराजों सात जी विद्वानों को अवश्य

आज डिक्टेट स्वास्थ्य का दृष्टि से छन पान के पान के लिए जोर देते हैं, जबकि जैनदर्शन स्वास्थ्य के साथ जीवदया का भी पालन करने का निर्देश करता है। कहा प्रचलन खूब हा गया ह, वहाँ तक दखा गया ह इक एक तरफछाना पानी रखा हो दूसरी तरफ बोतल बंद/आरओ का पानी तो लोग बोतल बंद/आरओ का पानी पीना सभा मूल्य मुनराजा, माता जा, विद्वाना का अवश्य ध्यान देना होगा अन्यथा आने वाली पीढ़ी तो इससे अनजान ही हो जाएगी।

